



प्राधिकरण  
के लिए गले की  
हड्डी बन गया है  
यह बस  
टर्मिनल

राइजिंग इन्दौर

■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया इंटर स्टेट बस टर्मिनल संचालन और संधारण के लिए ठेके पर नहीं जा पा रहा है। इस स्थिति में प्राधिकरण के द्वारा अब पांचवीं बार टेंडर जारी किया गया है। यह बस टर्मिनल प्राधिकरण के गले की हड्डी बन गया है।

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा ग्राम कुमेडी में 100 करोड़ रुपए की लागत से बेहतरीन बस टर्मिनल बनाया गया है। किसी एयरपोर्ट की बिल्डिंग को चुनौती देने में भी यह टर्मिनल सक्षम है। इस टर्मिनल को पूरा एयर कंडीशनर वाला बनाया गया है। जबसे यह बस टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है तबसे प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा इसे संचालन साधारण के लिए निजी क्षेत्र की एजेंसी को देने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश अभी तक नाकाम रही है। प्राधिकरण के द्वारा चार बार टेंडर डाल दिए जाने के बावजूद उसे एजेंसी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण में अब पांचवीं बार के टेंडर जारी कर दिए हैं।

इस बस टर्मिनल में सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्राधिकरण एक ही एजेंसी से पूरे बस टर्मिनल की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, वहां बनाई गई दुकानों को किराए पर देने का काम और वहां से संचालित होने वाली बसों से शुल्क की वसूली का काम करवाना चाहता है। बस टर्मिनल के संचालन का कार्य करने वाली एजेंसी का कहना है कि इस पूरे काम में अलग-अलग काम से कम तीन एजेंसी लगाई जाना चाहिए। साफ सफाई, पानी और ड्रेनेज के काम के लिए अलग एजेंसी होना चाहिए। दुकानों को किराए पर देने और उनसे किराया लेने के लिए अलग एजेंसी होना चाहिए और बसों के संचालन की व्यवस्था को अंजाम देने के लिए अलग एजेंसी होना चाहिए।

## 100 करोड़ के ISBT के लिए प्राधिकरण ने जारी किया पांचवीं बार टेंडर



इस स्थिति को अभी तक इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी समझने के लिए तैयार नहीं है। इन अधिकारियों के द्वारा तो कार्य के अनुभव और आर्थिक क्षमता के आधार पर ही एजेंसी के चयन के काम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इस स्थिति का ही यह परिणाम है कि यह बस टर्मिनल तैयार होने के महीनों बाद तक चालू होने की स्थिति में नहीं आ पाया है। अभी भी प्राधिकरण के द्वारा जो पांचवा टेंडर जारी किया गया है उसमें भी इस बात के आसार बहुत कम है कि कोई एजेंसी जाकर प्राधिकरण के द्वारा तय की गई शर्तों पर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगी।

### चावड़ा द्वारा बनाया गया इनक्यूबेशन सेंटर भी ताले में

प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण की योजना क्रमांक 140 में स्थित बिल्डिंग आनंद वन में इनक्यूबेशन सेंटर बनाया गया था। इस केंद्र को बनाने पर प्राधिकरण ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उस समय दावा यह किया गया था कि इस केंद्र के माध्यम से स्टार्टअप को काम करने का मौका मिलेगा। स्टार्टअप की मदद के लिए बनाया गया यह इनक्यूबेशन सेंटर अब धूल खा रहा है। यह सेंटर पिछले 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। प्राधिकरण के द्वारा इसके संचालन के लिए निजी क्षेत्र की एजेंसी को बुलाने की कोशिश की गई थी। कोई एजेंसी यह सेंटर चलाने के लिए नहीं आई। उपयोग नहीं होने से यह सेंटर बंद पड़ा हुआ ही खराब हो रहा है। अब तो इस केंद्र का इंटीरियर भी खराब होना शुरू हो गया है। इसके संचालन के लिए शहर के प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को भी जोड़ने की योजना थी लेकिन इनमें से भी किसी ने भी इस काम में रुचि नहीं दिखाई है।

### शहीद पार्क शुरू होने के इंतजार में



प्राधिकरण के द्वारा रिंग रोड पर खजराना चौराहे के पास में शहीद पार्क बनाया गया। यह पार्क उस समय बनाया गया था जब वर्तमान सांसद शंकर लालवानी प्राधिकरण के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय प्राधिकरण के संचालक मंडल में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे राजेश उदावत ने इस काम में सबसे ज्यादा रुचि ली थी। प्राधिकरण के द्वारा करीब 4-30 करोड़ रुपए खर्च कर इस शहीद पार्क का निर्माण किया गया था। यह सहित पार्क बनने के बाद से ही संचालन शुरू होने के इंतजार में है। शुरुआत में तो कहा गया था कि बीएसएफ के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। जब यह शहीद पार्क बनकर तैयार हुआ तो बीएसएफ ने इसे लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद महू मिलिट्री के माध्यम से इसका संचालन शुरू करने की कोशिश की गई लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। फिर प्राधिकरण ने यह सहित पार्क इंदौर नगर निगम को सौंपने की पहल की लेकिन निगम भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब इस शहीद पार्क में ताले लगे हुए हैं और कोई भी इसका संचालन करने के लिए तैयार नहीं है।

# भागीरथपुरा को भुलाने के लिए अब राष्ट्रीय मुद्दों पर इंदौर में आंदोलन शुरू

भागीरथपुरा में दूषित जल से 35 लोगों की मौत होने के मामले को भुलाने की दिशा में तेज प्रयास शुरू हो गए हैं। इन प्रयासों के तहत भाजपा ने इंदौर में राष्ट्रीय मुद्दे पर आंदोलन किया। इस आंदोलन में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थर टमाटर चले और राजनीति का वातावरण गर्म हो गया। यह सारी गर्मी एक अलग संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए थी।

राजिग इन्दौर  
रिपोर्टर

शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा शहर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के पहले मोर्चा के अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने जिला प्रशासन से विरोधी पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन करने की अनुमति ली। यह अनुमति देने के बाद पुलिस ने बेरी कटिंग कर ऐसी व्यवस्था को आकार देने की कोशिश की जिसके चलते दोनों दलों के कार्यकर्ता है एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहे। पुलिस की यह व्यवस्था निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दलों की विचारधारा को मानने वालों के बीच के संघर्ष को रोकने की पहल थी। यहां तक तो सब कुछ सही चला। गड़बड़ी की शुरुआत उस समय हुई जब प्रदर्शन शुरू हुआ। इस प्रदर्शन के पहले ही कांग्रेस के कार्यालय पर भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जमा हो गए थे। दूसरी तरफ युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता भी भाग लेने के लिए पहुंच गए थे।

इस आंदोलन के शुरू होते ही पत्थर टमाटर चलने लगे। दोनों दल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। दोनों दल के नेताओं का कहना है कि पत्थर चलाने की शुरुआत दूसरे पक्ष से हुई। पुलिस दोनों दलों की बात को सुन रही है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को भी नहीं मालूम कि यह शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस घटना में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल से कुछ लोगों की तो मलम पट्टी करने के बाद



छुट्टी हो गई। कुछ लोगों को भर्ती किया गया है। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अश्लील इशारे सभी को बुरे लगे हैं।

यह पूरा आंदोलन इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली में आयोजित किए गए विश्व स्तरीय सम्मेलन में वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर विरोध किया था। दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा किए गए विरोध का इंदौर में जवाब देने की कोशिश की गई। भागीरथपुरा के जल हादसे के मामले में पूरी तरह खामोश रहा भाजपा और युवा मोर्चा का संगठन दिल्ली के मामले को लेकर आक्रोशित नजर आया। इस प्रदर्शन से 1 दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान भागीरथपुरा के मामले को लेकर सदन में खूब चर्चा हुई। इस चर्चा में कांग्रेस के विधायकों ने इतने सवाल उठाए कि उनका कोई जवाब सरकार के पास नहीं था। बार-बार सरकार ने चर्चा से बचने के लिए मामले की जांच न्यायिक आयोग के द्वारा किए जाने की बात कही और

अपने आप को पीछे कर लिया। अब इस मामले को जनता की चर्चा से बाहर करने के लिए आवश्यक था कि इससे बड़ा कोई विवादित मामला हो जाए। इसीलिए दिल्ली की घटना पर इंदौर में प्रदर्शन हो गया और राजनीतिक संघर्ष की मसालेदार खबर सामने आ गई।

## कांग्रेस को भी दिखाई भारत अमेरिका ट्रेड डील

ऐसा नहीं है कि भाजपा को ही राष्ट्रीय मुद्दा दिखा और उसने इंदौर में आंदोलन कर दिया। कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है। भागीरथपुरा के मुद्दे पर न्याय यात्रा निकालने और सदन में सत्ता पक्ष को घर लेने के बाद कांग्रेस के द्वारा प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से बताया गया कि यह डील किसानों के विरोध में है। इस आंदोलन को किसान महापंचायत का नाम दे दिया गया।

## कैलाश जी जनता वाकई अनपढ़ है...

राजिग इन्दौर  
पंकज मुकाती

### घंटा, औकात, अनपढ़ ...

ये शब्द हैं मध्यप्रदेश के संसदीय कार्य, नागरीय निकाय मंत्री के। ये पत्रकारों के सवाल पर उनको घंटा कहते हैं। अडानी का नाम आने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहो कहते हैं। जब कोई उनकी विधानसभा में जहरीले पानी से मौत पर सवाल करे तो कह देंगे जनता अनपढ़ है।

ये भाषा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की है जो बच्चों को संस्कारी बनाने का ज्ञान देते हैं। जो लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हैं। इनकी खुद की भाषा किसी बाउंसर से कम नहीं। जुबान एक बार फिसलती है, पर बार बार लगातार ऐसी भाषा जुबान की फिसलन नहीं वैचारिक फिसलन कही जा सकती है। ये उसी जनता को अनपढ़ कह रहे हैं जिसने इन्हे तीन दशक से सर आंखों पर बैठा रखा है। वोटो से नवाजा है।

32 मौत के बाद भी जनता कैलाश जी, कैलाश जी, कैलाश जी कहती घूमती रही है और कैलाश जी उन्हें अनपढ़ कर



रहे हैं। भागीरथपुरा में 32 जिनदगियों के खत्म हो जाने पर भी किसी भी आम आदमी ने मंत्रीजी को कोई गलत शब्द नहीं कहे। अब मंत्रीजी उसी जनता को अनपढ़ बता रहे हैं। यानी वोट देने वाले, आपको सम्मान देने वाले आपकी निगाह की शरम रखने वालों को आप कुछ भी

कहने को आजाद हैं। ये एक से जनता को गुलाम समझने की मानसिकता है।

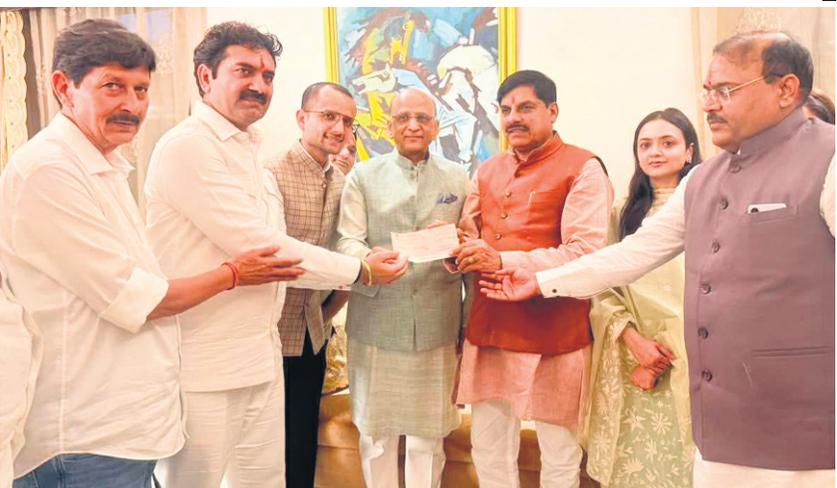
कैलाश विजयवर्गीय ने सिर्फ भागीरथपुरा के लोगों को सिर्फ अनपढ़ ही नहीं कहा उनके पूरे जीवनस्तर पर सवाल उठाया है। भागीरथपुरा को मुंबई की धारावी जैसा बता दिया। यहां के लोगों को काम में अड़गे लगाने वाला तक कह दिया। वे सदन में बोले ये छोटी बस्ती है, लोग अनपढ़ है। नगरनिगम तो पाइप लाइन कब से बदलना चाह रही है। पर इस बस्ती के लोगों के बीच जाकर काम करना मुश्किल है। वाकई, ये बस्ती सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। ऐसे अनपढ़ और काम में अड़गे डालने वालों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए।

मान लेते हैं कैलाश जी कि भागीरथपुरा के लोग अशिक्षित हों, अनपढ़ हों, निरक्षर हों तो क्या अनपढ़ लोगों को जीने का हक नहीं। आप उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। क्या आप उन्हें गटर का पानी पिलाकर मार देंगे। क्या अशिक्षित लोगों को जिनदगी का अधिकार नहीं। पहले घंटा, फिर औकात, फिर अनपढ़... कैलाश जी आपको हो क्या गया। कहीं वाकई आपकी जुबान पर शनि की दशा तो नहीं चल रही या आपको दिल्ली से खबर हो गई है बदलती हुई दशा की। जिसकी खीझ आपके व्यवहार में झलक रही है। वाकई जनता अनपढ़ है कैलाश जी तभी तो उसने आपको लगातार चुन लिया। आपका वोट है आप ज्यादा बेहतर जानते हैं।

### कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा सदन में-

मुंबई की धारावी से भागीरथपुरा की तुलना करते हुए कहा कि ये 90 साल पुरानी बस्ती है। यहां अशिक्षित लोग रहते हैं, जहां काम करना नगर निगम कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता है। इसी कारण कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। महापौर ने टेंडर जारी किए थे, लेकिन काम समय पर शुरू नहीं हो पाया।

## गए थे शोक प्रकट करने उद्योगपति ने थमाया एक करोड़ का चेक



इंदौर। रविवार को इंदौर में सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उद्योगपति विनोद अग्रवाल के निवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। अग्रवाल की पत्नी नीना अग्रवाल का पिछले दिनों निधन हो गया था। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय को छोड़कर भाजपा के ज्यादातर वरिष्ठ नेता थे। संवेदना प्रकट करने के बाद जब मुख्यमंत्री लौटने लगे तो अग्रवाल ने उन्हें एक चेक सौंपा जिसे देख कर वे चौंक पड़े। एक करोड़ रुपए का यह चेक भाजपा संगठन के लिए था। यह राशि संगठन सशक्तिकरण के लिए समर्पण निधि के रूप में भेंट की गई है।

राजिग इन्दौर

रिपोर्टर

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एमबीए करने वाली नेहा सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित कॉन्वलेव में शर्मसार कर दिया।

इस युवती ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से भाग लेते हुए चीन के द्वारा बनाए गए मॉडल को अपने विश्वविद्यालय का मॉडल बता दिया। जब इस मामले की कलई खुली तो पूरे देश को नीचा देखना पड़ा।

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में रोबोट डॉग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक प्रोफेसर को बलि का बकरा बना दिया। यह मामला तब शुरू हुआ जब समिट में यूनिवर्सिटी की ओर से पहुंची प्रोफेसर नेहा सिंह ने डीडी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनके पवेलियन में दिखाया गया रोबोटिक डॉग यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने खास इस कार्यक्रम के लिए बनाया है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने जल्द ही दावा किया कि यह रोबोट यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि चीन की कंपनी nitree Robotics का बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसका नाम Unitree Gow है और यह बाजार में पहले से बिक रहा है।

जो इस यूनिवर्सिटी की उपलब्धि बताई जा रही थी वही उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई। इस मामले को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भारत मंडपम में चल रहे कार्यक्रम से यूनिवर्सिटी के सेंटर को हटा दिया गया। 18 फरवरी को यूनिवर्सिटी ने सार्वजनिक माफी जारी की। बयान में कहा गया कि रोबोट यूनिवर्सिटी की अपनी खोज नहीं है और संस्था

# इंदौर में शिक्षित नेहा ने कर दिया शर्म सार

ने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। साथ ही यह भी कहा गया कि पवेलियन पर मौजूद एक प्रतिनिधि को पूरी जानकारी नहीं थी और बिना अनुमति मीडिया से बात कर बैठी। यूनिवर्सिटी के बयान में कहा गया कि कैमरे पर आने के उत्साह में प्रतिनिधि ने गलत जानकारी दे दी, जबकि उन्हें प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं थी। आयोजकों की भावना का सम्मान करते हुए यूनिवर्सिटी ने स्टॉल खाली कर दिया।

माफी के इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटी अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और सारा दोष एक महिला प्रोफेसर पर डाल दिया गया है। एक यूजर ने लिखा कि नेहा जी को बलि का बकरा बना दिया गया है। अगर



हमारी यूनिवर्सिटी 'प्रधानमंत्री' के विजन और मिशन पर काम कर रही है।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ. ऐश्वर्या श्रीवास्तव

उन्हें बोलने की अनुमति नहीं थी, तो फिर उन्हें वहां क्यों भेजा गया?

## गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के माडल को अपना बताया...

### क्या प्रोफेसर नेहा सिंह की नौकरी गई?

विवाद के बाद नेहा सिंह ने अपने लिंकडइन प्रोफाइल पर "Open to Work" लिख दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह नई नौकरी की तलाश में हो सकती हैं। इस कदम को भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मिली और कई लोगों ने इसे इस बात का संकेत माना कि उन्हें पेशेवर नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ ने दावा किया उन्हें शायद नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि, यूनिवर्सिटी की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े मंच के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट को यूनिवर्सिटी की खुद की खोज बताना उसकी साख भारी पड़ गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी अब भी कह रही है कि उसने कभी रोबोट को अपनी खोज नहीं बताया, लेकिन टीवी इंटरव्यू, उसके बाद माफी और फिर स्टॉल खाली करने की घटना- इन सबने मिलकर विवाद को और बढ़ा कर दिया है।

केग की विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में खुलासा, दूसरे शहरों ने नहीं बताया उपयोग

# आश्रय निधि के 163 करोड़ का निगम में दुरुपयोग

इंदौर इंदौर नगर निगम में आश्रय निधि के तहत कॉलोनाइजर्स के द्वारा जमा किए गए 163 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया है। प्रदेश के दूसरे शहरों में आश्रय निधि के पैसे के उपयोग की जानकारी ही उजागर नहीं की।

यह खुलासा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट कल विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि कॉलोनाइजर्स के द्वारा अपने कॉलोनी के विकास में यदि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भवन अथवा प्लॉट आरक्षित नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कॉलोनाइजर आश्रय निधि की राशि जमा कर सकता है। यह राशि संबंधित शहर की नगर निगम में जमा की जाती है। इंदौर नगर निगम में कॉलोनाइजर्स के द्वारा आश्रय निधि के तहत 163 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। जब इस राशि के उपयोग की जानकारी केग के द्वारा ली गई तो निगम के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस राशि का



उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के भावनाओं का निर्माण करने में कर लिया है। केग ने अपनी रिपोर्ट में कहा

है कि इंदौर नगर निगम के द्वारा किया गया उपयोग दरअसल इस राशि का दुरुपयोग है। केग ने कहा कि

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलग से बजट होता है ऐसे में इस काम में आश्रय निधि के पैसे को लगाना मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1998 के प्रावधानों के खिलाफ है। इस रिपोर्ट से यह हकीकत भी उजागर होकर सामने आई है कि इंदौर ने तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में इस पैसे को लगाया लेकिन दूसरे बड़े शहरों नहीं इस योजना के तहत प्राप्त हुए पैसे का क्या किया, यह भी नहीं बताया है। आश्रय निधि के तहत भोपाल को 43, ग्वालियर को 11, जबलपुर को 28 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यह मामला आश्रय निधि के 2018 से 2023 तक जमा हुई राशि का है।

संपादकीय...



## प्राधिकरण को अपने कार्यों पर फिर से विचार करना होगा

**इंदौर** विकास प्राधिकरण के द्वारा करोड़ रुपए खर्च कर योजना तैयार की जाती है और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। प्राधिकरण के द्वारा करोड़ों रुपए लगाकर तैयार किए गए प्रोजेक्ट संचालित करने के लिए संकट में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि प्राधिकरण के द्वारा अपने कार्यों पर फिर से विचार किया जाए। प्राधिकरण के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है वह पैसा निश्चित तौर पर इंदौर की जनता के द्वारा प्राधिकरण की संपत्ति अपने नाम पर लेकर प्राधिकरण को दिया जाता है। ऐसे में प्राधिकरण को उसे पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्राधिकरण को शहर



■ गौरव गुप्ता

की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी इस तरह की योजनाएं तैयार करना चाहिए जिनका संचालन संधारण आसानी के साथ हो सके। ऐसी योजनाएं क्रेन की नहीं करना चाहिए जो कि बाद में प्राधिकरण के ही गले की हड्डी बन जाए। इस समय प्राधिकरण के द्वारा तैयार की गई बहुत सारी संपत्ति आवंटन के इंतजार में है। प्राधिकरण के द्वारा कई बार टेंडर जारी कर दिए जाने के बावजूद इन संपत्ति का संचालन संचालन करते हुए जनता को इनका लाभ दिलाने के लिए कोई भी ठेकेदार फर्म तैयार नहीं हो रही है। ऐसे में प्राधिकरण को चाहिए कि वह अपने कामकाज की खुद समीक्षा करें और उसके आधार पर आगे के लिए योजना तैयार करें।

# पार्टनर होना अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं, परिवाद में विशिष्ट भूमिका का उल्लेख अनिवार्य: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत एक पार्टनरशिप फर्म और उसके साझेदारों को बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता आरोपी के साथ किसी भी कानूनी ऋण या दायित्व (legal debt or liability) के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहा। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि परिवाद में साझेदारों की विशिष्ट भूमिका के बारे में स्पष्ट आरोप नहीं लगाए गए थे।

### प्रकरण इस प्रकार था की

यह अपील विजयकांत मोतीलाल कोठारी (अपीलकर्ता) द्वारा महाराष्ट्र राज्य और ओम इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स तथा उसके भागीदारों (प्रतिवादी संख्या 2 से 7) के खिलाफ प्रस्तुत की गई थी। परिवाद के अनुसार, जुलाई 2004 में हीराचंद रायचंद पगारिया नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से 56,50,000 रुपए का हेंड लोन लिया था। आरोप था कि पगारिया के



करीबी दोस्त होने के नाते आरोपियों ने ऋण चुकाने की जिम्मेदारी ली थी। इसके तहत, प्रतिवादी संख्या 3 (मूल आरोपी संख्या 2) ने कथित तौर पर 31 जनवरी 2006 को बैंक ऑफ बड़ौदा का 78,00,000 रुपए का चेक शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किया।

चेक बाउंस होने और कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर उक्त परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), पुणे ने 1 मार्च 2008 को आरोपियों को दोषी ठहराया था। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे ने 31 जनवरी 2011 को अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दो मुख्य कानूनी मुद्दों पर विचार किया-

क्या यह साबित किए बिना कि चेक किसी तीसरे पक्ष (Third Party) के दायित्व को पूरा करने के लिए जारी किया गया था, धारा 138 का अपराध बनता है?

क्या शिकायत में विशिष्ट भूमिका बताए बिना किसी पार्टनर पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

साझेदारों की जिम्मेदारी पर कोर्ट ने कहा कि शिकायत में केवल यह एक सामान्य कथन था कि आरोपी फर्म के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। सुप्रीम कोर्ट के कमलकिशोर

श्रीगोपाल तापड़िया बनाम इंडिया एनर्जी-जेन प्राइवेट लिमिटेड (2025) और एन.के. वाही बनाम शेखर सिंह (2007) के निर्णय का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि केवल 'पार्टनर' या 'डायरेक्टर' का पद होना पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने एन.के. वाही मामले का उल्लेख करते हुए कहा- कथित निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए, शिकायत में लेन-देन में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विशिष्ट आरोप होना चाहिए किसी भी दावे या विशिष्ट सबूत के अभाव में शिकायत विचारणीय नहीं होगी।

हाईकोर्ट ने पाया कि मुख्य परीक्षक (chief-examination) में दिए गए सामान्य बयान के अलावा, ऐसा कोई दस्तावेजी

रिकॉर्ड नहीं था जो यह साबित कर सके कि आरोपियों ने पगारिया की देनदारी अपने ऊपर ली थी। कोर्ट ने विसंगति को रेखांकित करते हुए कहा-

शिकायतकर्ता यह समझने में असमर्थ है कि श्री पगारिया द्वारा लिया गया 56,50,000 रुपए का हेंड लोन बढ़कर 78,00,000 रुपए कैसे हो गया, जो कि अनादरित चेक की राशि है। राशि में वृद्धि को सही ठहराने के लिए ब्याज दर के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

कोर्ट ने सत्र न्यायालय के इस निष्कर्ष को सही माना कि चेक जारी करने से पहले शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच कोई वित्तीय संबंध नहीं था और उनके बीच कोई

'प्रिवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट' (privity of contract) नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (राजेश प्रसाद बनाम बिहार राज्य और एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य) का हवाला देते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि अपीलीय अदालत को बरी करने के फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि फैसला पूरी तरह से विकृत (patent perversity) न हो या सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा न गया हो। कोर्ट ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद आरोपी के पक्ष में निर्दोष होने की दोहरी धारणा (double presumption of innocence) होती है।

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों का शिकायतकर्ता के प्रति कोई कानूनी ऋण या दायित्व नहीं था। इसके अलावा, ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह दर्शाता हो कि पगारिया की देनदारी लेने से जुड़े व्यवसाय के संचालन के लिए कौन सा भागीदार जिम्मेदार था। हाईकोर्ट ने माना कि सत्र न्यायालय के फैसले में कोई कमी नहीं है और अपील को खारिज कर दिया। केस- विजयकांत मोतीलाल कोठारी बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य

निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत, तब एक भागीदार (partner) दायित्व रखता है जब चेक फर्म की ओर से किसी वैध देनदारी के लिए जारी किया गया हो और वह चेक बाउंस हो जाए। केवल पार्टनर होने से दायित्व नहीं बनता; पार्टनर का चेक जारी करने के समय व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होना आवश्यक है।

### पार्टनर की जवाबदेही

#### (Liability) के मुख्य बिंदु-

**सक्रिय भूमिका-** पार्टनर को फर्म के दैनिक कार्यों या चेक जारी करने की प्रक्रिया में जिम्मेदार होना चाहिए।

**चेक बाउंस का कारण-** चेक अपर्याप्त धनराशि (insufficient funds) या अन्य कारणों से बाउंस हुआ हो।

**कानूनी नोटिस -** चेक बाउंस होने के बाद 30 दिनों के भीतर वैधानिक नोटिस भेजा गया हो।

**संयुक्त और पृथक दायित्व-** फर्म और उसके सक्रिय पार्टनर, दोनों चेक की राशि के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, केवल पदनाम (designation) के आधार पर पार्टनर को अपराधी नहीं माना जा सकता, जब तक कि शिकायत में उसकी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख न हो।

# क्या फर्क है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में



## 3. जेरूसलम आर्टिचोक

जिसे सन रूट, सनचोक या अर्थ एप्पल के नाम से भी जाना जाता है—सूरजमुखी परिवार का हिस्सा है। इसमें भी कई पोषक तत्व होते हैं। इनुलिन युक्त आहार फाइबर होता है, अन्य फायदों के साथ-साथ, इनुलिन आपके कोलन में लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। यह आपकी बड़ी आंत में खनिजों के अवशोषण में भी सहायक हो सकता है।

## 4. लहसुन

लहसुन आंत में लाभकारी बिफिडोबैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देकर प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। यह रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है।

## 5. प्याज

प्याज के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इनुलिन से भरपूर और फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड (एफओएस) भी होता है। एफओएस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो आंतों के फ्लोरा को मजबूत करने और वसा

के विघटन में मदद करता है।

## 6. लीक

लीक प्याज और लहसुन के ही परिवार से आते हैं। लीक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, यानी इनमें कैलोरी कम होती है लेकिन विटामिन और खनिज अधिक मात्रा में होते हैं। इनमें मौजूद इनुलिन की वजह से लीक स्वस्थ आंत के बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और वसा को पचाने में मदद करते हैं।

## 7. शतावरी

शतावरी प्रीबायोटिक्स का एक और बेहतरीन स्रोत है। इस पौष्टिक सब्जी में प्राकृतिक रूप से इनुलिन पाया जाता है।

## 8. केले

केले में कुछ मात्रा में इनुलिन भी पाया जाता है। कच्चे (हरे) केले में प्रतिरोधी स्टार्च की मात्रा भी अधिक होती है। इसके अलावा, केले में कई अन्य यौगिक भी पाए जाते हैं।

## 9. जौ

जौ में बीटा-ग्लूकन दिखाया गया है। यह कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को घटाने में सहायक। यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने

में भी मदद कर सकता है।

## 10. जई

साबुत जई एक पौष्टिक अनाज है जिसमें प्रीबायोटिक गुण होते हैं। बीटा-ग्लूकन फाइबर और विभिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

## 11. सेब

सेब में पेक्टिन होता है, जो एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है। पेक्टिन, ब्यूटिरेट की मात्रा बढ़ाता है, जो एक अल्प-श्रृंखला वाला फैटी एसिड है और आंत में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया को पोषण देता है तथा हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या को कम करता है।

## 12. कोन्जैक की जड़

जिसे हाथी याम के नाम से - या आलू की तरह जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी है। इस कंद से बने आटे में 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत विश्वसनीय स्रोत ग्लूकोमैनन फाइबर नामक एक अत्यधिक चिपचिपे आहार फाइबर है, यह आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देकर प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है।

## 13. कोको

कोको बीन्स थियोब्रोमा कैकाओ पेड़ के बीज होते हैं जिनका उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। कोको पाउडर की मदद से ओटमील, स्मूदी, दही और अन्य व्यंजनों में कोको मिलाना आसान हो जाता है। इसमें पॉलीफेनॉल, जैसे कि फ्लेवोनॉल्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी प्रभाव डालते हैं। विश्वसनीय स्रोत ये यौगिक हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करते हुए लाभकारी आंत बैक्टीरिया को बढ़ाने में भी मदद करते हैं।

## 14. बर्डक की जड़

बर्डक की जड़ जापान में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। बर्डक की जड़ इनुलिन और एफओएस से भरपूर होती है, जो पाचन तंत्र में स्वस्थ बैक्टीरिया के विकास में सहायक होते हैं। इसमें फेनोलिक यौगिक भी पाए जाते हैं।

## 15. अलसी के बीज

अलसी के बीजों में मौजूद फाइबर स्वस्थ आंत बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और इसमें फेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होता है।

## 16. यार्कॉन की जड़

यह शकरकंद से काफी मिलती-जुलती एक सब्जी है जो फाइबर से भरपूर होती है। इसमें प्रीबायोटिक FOS और इनुलिन मौजूद हैं।

साथ ही इसमें फेनोलिक यौगिक भी होते हैं जो इसे एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं।

## 17. जिंकामा की जड़

जिंकामा की जड़ में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जिसमें प्रीबायोटिक फाइबर इनुलिन भी शामिल है। यह पाचन स्वास्थ्य में सुधार, इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि और रक्त शर्करा के स्तर में कमी कर सकती है।

## 18. गेहूं का चोकर

गेहूं का चोकर साबुत गेहूं के दाने की बाहरी परत होती है। इसमें अरबिनोक्सिलन ऑलिगोसैकेराइड (AXOS) से बना एक विशेष प्रकार का फाइबर होता है। गेहूं के चोकर से प्राप्त एक्सोस फाइबर आंत में स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ है, जिससे स्वस्थ व्यक्तियों में, जिनकी पाचन क्रिया धीमी थी, मल नरम हो जाता है।

## 19. समुद्री शैवाल

समुद्री शैवाल प्रीबायोटिक्स से भरपूर विश्वसनीय स्रोत, साथ ही अन्य स्वास्थ्यवर्धक यौगिक विश्वसनीय स्रोत है कि समुद्री शैवाल में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड, शॉर्ट-चेन फैटी एसिड (एससीएफए) के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जो आपकी आंत की परत बनाने वाली कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं।

## 20. एवोकैडो

सेब की तरह, एवोकाडो इसमें पेक्टिन होता है विश्वसनीय स्रोत जिसमें प्रीबायोटिक गुण होते हैं। नियमित रूप से एवोकाडो खाने से मल में पित्त अम्ल का स्तर कम करने, स्वस्थ वसा अम्ल और लघु-श्रृंखला वसा अम्ल का स्तर बढ़ाने और आंत में अच्छे बैक्टीरिया की उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

## प्रीबायोटिक के मुख्य स्रोत-

**फल और सब्जियां-** केला (विशेषकर कम पका हुआ), सेब, जामुन, प्याज, लहसुन, लीक, शतावरी।

**साबुत अनाज और दालें-** जई (Oats), जौ, बीन्स, दाल, और चने।

**अन्य-** बादाम, अलसी के बीज और अलसी का तेल।

## प्रीबायोटिक्स के स्वास्थ्य लाभ-

**बेहतर पाचन-** आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं।

**पोषक तत्वों का अवशोषण-** कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स को अवशोषित करने में मदद करते हैं, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद हैं।

**प्रतिरक्षा प्रणाली-** समग्र प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं। सूजन कम करना- पेट में सूजन को दूर करने में सहायता करते हैं।

## प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में अंतर-

**प्रोबायोटिक-** जीवित अच्छे बैक्टीरिया जो दही, के फिर जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं।

**प्रीबायोटिक-** उन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन (फाइबर)।

**सिनबायोटिक्स-** जब प्री और प्रोबायोटिक्स को एक साथ लिया जाता है।

**सावधानी-** प्रीबायोटिक्स को सप्लीमेंट्स के बजाय प्राकृतिक खाद्य पदार्थों (जैसे उच्च फाइबर वाले फल और सब्जियां) के माध्यम से लेना बेहतर माना जाता है।

प्रीबायोटिक्स आंतों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और आपके समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आंतों का स्वास्थ्य एक चर्चित विषय बन गया है। और इसका कारण भी वाजिब है - एक स्वस्थ आंत आपके समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में, अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।

प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है, उसमें उनके अंतर, वे आपके आंतों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं।

आंत क्या है? हालांकि कई लोग पेट के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपकी आंत से तात्पर्य आपकी छोटी और बड़ी आंतों से है। आपकी आंत में सूक्ष्मजीवों का एक पूरा समुदाय रहता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक और वायरस - इसे माइक्रोबायोम कहा जाता है। जब आपका पेट स्वस्थ होता है, तो आपके पाचन तंत्र में हानिकारक बैक्टीरिया की तुलना में अच्छे बैक्टीरिया अधिक होते हैं। और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्वस्थ पेट भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को चयापचयित करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि एक स्वस्थ पेट हृदय स्वास्थ्य (उदाहरण के लिए, रक्तचाप को कम करके), मानसिक स्वास्थ्य और गुर्दे के कार्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

प्रीबायोटिक्स ऐसे अपचनीय फाइबर या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो आंत के अच्छे बैक्टीरिया (प्रोबायोटिक्स) के लिए ईंधन का काम करते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और पाचन स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ये जीवित सूक्ष्मजीव नहीं हैं, बल्कि वे भोजन हैं जो आंत के माइक्रोबायोटा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।

## आपको ये 20 सर्वश्रेष्ठ प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थ जरूर खाने चाहिये।

प्रीबायोटिक्स\* का मतलब ऐसे फाइबर होते हैं जो आंत में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें शॉर्ट-चेन फैटी एसिड बनाने में मदद मिलती है जो कोलन कोशिकाओं और चयापचय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं।

प्रीबायोटिक से भरपूर खाद्य पदार्थों के कुछ उदाहरणों में चिकोरी की जड़, प्याज, लहसुन, ओट्स, जौ, सेब और समुद्री शैवाल शामिल हैं। प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थ पाचन, आंत्र क्रिया और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में सहायक हो सकते हैं, और खाना पकाने से फाइबर के प्रभाव कम हो सकते हैं, इसलिए कच्चे विकल्प मददगार हो सकते हैं। प्रीबायोटिक्स आपके आंत के बैक्टीरिया को अनुमति देते हैं पोषक तत्वों का उत्पादन करें। विश्वसनीय स्रोत यह आपकी आंतों की कोशिकाओं के लिए फायदेमंद है, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है।

इन पोषक तत्वों में ब्यूटिरेट, एसीटेट और प्रोपियोनेट जैसे शॉर्ट-चेन फैटी एसिड शामिल हैं, जो आपके रक्तप्रवाह में अवशोषित हो सकते हैं और चयापचय स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं।

## 1. चिकोरी की जड़

चिकोरी की जड़ में मौजूद फाइबर का अधिकांश भाग प्रीबायोटिक फाइबर इनुलिन से आता है, जो पाचन क्रिया और आंत्र क्रिया में सुधार करता है और कब्ज से राहत दिलाने में सहायक होता है।

## 2. सिंघपर्णी के पत्ते

डंडेलियन के फूलों की पत्तियों को पकाकर या कच्चा भी खाया जा सकता है। वे फाइबर युक्त होते हैं।



डॉ. आरती मेहरा  
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ  
7999788456



राजिग इन्दौर  
रिपोर्टर

# AI कंटेंट पर सख्ती शुरू, नए आईटी नियम लागू

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से तैयार किए जा रहे फोटो, वीडियो और ऑडियो कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार से नए आईटी नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत एआई जनरेटेड कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डीपफेक या आपत्तिजनक सामग्री की सूचना मिलने के बाद उसे तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद डिजिटल दुनिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

## एआई कंटेंट लेबलिंग नियम क्या है?

नए नियमों के अनुसार यदि कोई फोटो, वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट एआई टूल की मदद से बनाया गया है तो उसे पोस्ट करते समय स्पष्ट रूप से एआई जनरेटेड या इसी तरह का लेबल दिखाना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दर्शक यह समझ सकें कि जो सामग्री वे देख रहे हैं वह वास्तविक घटना का दृश्य नहीं बल्कि तकनीक के जरिए तैयार की गई है।

सरकार का मानना है कि डीपफेक तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि आम व्यक्ति के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लेबलिंग से भ्रामक सूचना के खतरे को कम किया जा सकेगा।

## तीन घंटे में हटानी होगी डीपफेक सामग्री- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बढ़ी

नए प्रावधानों के तहत यदि किसी डीपफेक या अवैध एआई कंटेंट के बारे में सक्षम प्राधिकारी



द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे तीन घंटे के भीतर हटाना या उस तक पहुंच रोकना अनिवार्य होगा। पहले इस तरह की सामग्री हटाने के लिए अधिक समय दिया जाता था, लेकिन अब इसे काफी कम कर दिया गया है।

गंभीर मामलों में, जैसे बिना सहमति के किसी व्यक्ति की छवि से छेड़छाड़ या अश्लील डीपफेक, तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी। सरकार का तर्क है कि डीपफेक सामग्री कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, इसलिए त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।

## किन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे नियम?

ये नियम सभी प्रमुख सोशल मीडिया और इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे, जिनमें वीडियो शेयरिंग साइट, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग सेवाएं और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन कंपनियों को अब अपनी मॉडरेशन प्रणाली मजबूत करनी होगी और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष तंत्र विकसित करना होगा।

यदि कोई प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे इंटरमीडियरी सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वह

प्लेटफॉर्म यूजर द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

## बढ़ते डीपफेक मामलों पर चिंता

पिछले कुछ समय में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें सार्वजनिक हस्तियों, नेताओं और आम नागरिकों की छवियों का दुरुपयोग कर फर्जी वीडियो तैयार किए गए। इससे न केवल प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा बल्कि सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर भी असर पड़ा।

सरकार का कहना है कि एआई एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकना उतना ही आवश्यक है। नए नियमों के जरिए सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक जिम्मेदार बनाना चाहती है ताकि गलत सूचना और साइबर अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके।

## आम यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर असर

जो लोग एआई टूल की मदद से रील, शॉर्ट वीडियो, फोटो एडिट या अन्य डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, उन्हें अब स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सामग्री एआई से तैयार की गई है। यदि कोई यूजर जानबूझकर बिना लेबल के एआई कंटेंट पोस्ट करता है और वह भ्रामक साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

**डीपफेक पर  
लगाम, सोशल  
मीडिया को  
तीन घंटे में  
करना होगा  
एक्शन**

## यूजर्स को मिलेगा अधिक सुरक्षा कवच

आम सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए यह नियम राहत लेकर आ सकता है। उन्हें अब यह जानने का अधिकार मिलेगा कि जो सामग्री उनके सामने है वह वास्तविक है या तकनीक से तैयार की गई है। इससे फर्जी खबरों के प्रसार पर भी रोक लगने की उम्मीद है।

## डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि एआई कंटेंट लेबलिंग और तीन घंटे में डीपफेक हटाने का प्रावधान डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्लेटफॉर्म और सरकार के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक होगा।

आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि ये नियम कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या इससे वास्तव में डीपफेक और फेक न्यूज की समस्या पर अंकुश लगता है। फिलहाल इतना तय है कि डिजिटल दुनिया में एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने सख्त नियामक ढांचा अपनाकर एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ ही स्वीकार्य होगा।

# विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को लिखी चिट्ठी, कहा- आओ, पश्चिम बंगाल को फिर से करें जिंदा.

राजिग इन्दौर  
रिपोर्टर

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि भारत माता के वीर सपूत ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अथक प्रयासों से ही आज पश्चिम बंगाल भारत का एक अभिन्न अंग है। आइए, उनके सपनों के पश्चिम बंगाल को फिर से जिंदा करें और कंधे से कंधा मिलाकर 2026 में विकसित पश्चिम बंगाल बनाने की शपथ लें।

पीएम मोदी की यह चिट्ठी डोर-टू-डोर कैंपेन के दौरान पश्चिम बंगाल के

सभी लाभान्वित लोगों को बांटा जा रहा है। इस पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे पश्चिम बंगालवासियों, जय मां काली। अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोचे-समझे फैसले पर निर्भर करता है। मेरे सोनार बंगाल के सपने देखने वाला हर एक जवान, बूढ़ा और महिला आज बहुत पीड़ा में हैं। उनके पीड़ा से आज मेरा हृदय भी व्यथित है। इसलिए, मैंने मन की गहराइयों से एक संकल्प लिया है, पश्चिम बंगाल को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प।

## पीएम ने लिखा-राज्य की जर्जर

## हालत से व्यथित है मन

पीएम मोदी ने लिखा है कि स्वतंत्रता



के बाद पश्चिम बंगाल देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता था और औद्योगिक विकास में अग्रणी था। लेकिन आज इस गौरवशाली राज्य की जर्जर हालत देखकर मेरा मन व्यथित हो उठता है। पिछले छह दशकों के कुशासन और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल को ही अपूरणीय क्षति हुई है, उसे बयान नहीं किया जा सकता।

## घुसपैठियों का भी किया है जिक्र

पीएम मोदी ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद और ऋषि अरविंद ने जिस बंगाल का सपना देखा था, वह आज बोट बैंक की संकीर्ण राजनीति, हिंसा और अराजकता में जकड़ा हुआ है और यह हम सबके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। पश्चिम बंगाल की धरती के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी के ललकार ने कभी पूरे देश को प्रेरित किया था, आज उनकी ही पवित्र भूमि अवैध घुसपैठ और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से कलंकित है। कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर का सोनार बंगाल पर नकली वोटर हावी हो रहे हैं। अराजकता के अंधेरे में डूबते पश्चिम बंगाल को देखकर आज पूरा देश चिंतित है।

## एनडीए सरकार के काम गिनाए

पीएम मोदी ने लिखा है कि अब परिवर्तन अनिवार्य है। देश के कई राज्यों में आज जीवन स्तर बेहतर हुआ है, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आई है। आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। पश्चिम बंगाल भी इस विकास और प्रगति का पूरा हकदार है। पिछले 11 सालों में देशवासियों के आशीर्वाद को ताकत बनाकर मेरी सरकार ने जनकल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार के असहयोग और विरोध के बावजूद, आज पश्चिम बंगाल के करीब 5 करोड़ लोग जन-धन योजना के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। %स्वच्छ भारत अभियान% के तहत राज्य में 85 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।

## करोड़ों रुपए की बर्बादी के बीच बद्दहाल है गांधी हाल का फाउंटेन



इंदौर नगर निगम के द्वारा शहर की सुंदरता पर करोड़ों रुपए खर्च करने का काम किया जा रहा है। इस पैसे से किसी चौराहे को सुंदर बना रहे हैं तो किसी चौराहे पर फाउंटेन लगा रहे हैं। इसके बीच शहर के ऐतिहासिक स्थल गांधी हाल के सामने लगा हुआ फाउंटेन अपनी बद्दहाली पर आंसू बहता हुआ नजर आ रहा है। इस फाउंटेन की हालत बद्द से बद्दतर है। इंदौर नगर निगम के सक्रिय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस स्थिति से कोई सरोकार नहीं है। वे लोग तो खामोशी के साथ इस नजारे को देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं।

## इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू मशीनों से खुदाई कर किया जा रहा मिट्टी परीक्षण

राजिग इन्दौर  
रिपोर्टर

इंदौर। इंदौर के बहुचर्चित बीआरटीएस मार्ग पर एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतर चुका है। 15 साल पहले यूपीए सरकार के शासनकाल में मंजूर हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार असमंजस की स्थिति रही, क्योंकि बीआरटीएस का निर्माण इस एबी रोड पर हो चुका था। अब एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए जाने के बाद कॉरिडोर पर बैरिकेड लगा दिए गए।

बीआरटीएस पर एलिवेटेड कॉरिडोर की प्लानिंग, ट्रैफिक सर्वे, मिट्टी परीक्षण पर ही पांच करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई। अब फिर से मिट्टी परीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल एलआईजी गुरुद्वारा के पास बैरिकेड लगाए गए हैं। छह किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को



बनाने में तीन साल का समय लगेगा। एलिवेटेड कॉरिडोर का ठेका गुजरात के राजकमल बिल्डर्स को 2021 में दिया गया था। यह कॉरिडोर 2024 तक बन जाना था, लेकिन सर्वे में ट्रैफिक लोड 4 प्रतिशत आने के कारण मामला अटका रहा। तय अनुबंध के तहत यदि लोक निर्माण विभाग ब्रिज बनाने की योजना रद्द करता तो उसे कंपनी को 30 करोड़ रुपये चुकाना पड़ते, लेकिन दो माह पहले फिर प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया और अब काम आगे बढ़ रहा है।

### 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे

एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। कॉरिडोर एलआईजी चौराहे से नवलखा चौराहे तक छह किलोमीटर लंबाई में बनेगा। पिछले दिनों इस प्रोजेक्ट को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जनप्रतिनिधियों की बैठक ली थी। तब यह फैसला लिया गया था कि एलिवेटेड कॉरिडोर के तीन चौराहों पर भुजाएं उतारे जाने के अलावा रोटर भी बनाई जाएगी।



## कॉलेज की ओपन जिम अटाला हो गई

राजिग इन्दौर  
रिपोर्टर

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सर्सेस के रूप में पहचाने जाने वाले शासकीय कला एवं कॉमर्स महाविद्यालय के परिसर में लगी हुई ओपन जिम अटाला हो गई है। यह जिम विद्यार्थियों के कसरत करने के लिए लगाई गई थी। इस जिम के सभी उपकरण टूट गए हैं। इस तरफ ना तो महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ना ही किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान है। अब जब कोई वीआईपी इस कॉलेज में किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आएगा तो उस समय पर रातों-रात इस जिम को अच्छा कर दिया जाएगा। कॉलेज के विद्यार्थी उसी दिन के आने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।



## होली पर ग्रहण और सूतक का साया पंडितों ने बताए शुभ मुहूर्त

इस वर्ष होलिका दहन और धुलेंडी की तारीखों पर असमंजस बना हुआ है। दोनों ही तारीखों को लेकर ज्योतिषाचार्यों के अलग-अलग मत हैं। इस असमंजस का मुख्य कारण है 3 मार्च को लगने वाले चंद्रग्रहण और सूतक काल। इस विषय पर हमने प्रमुख पंडितों और ज्योतिषाचार्यों से बात की और जाना कि किस समय होलिका दहन करना और धुलेंडी खेलना उचित रहेगा।

**पूर्णिमा प्रदोषकाल में होती है तभी होलिका दहन होना चाहिए-** शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनायक पांडे ने बताया कि होलिका दहन दो मार्च को ही होगा। क्योंकि धर्मशास्त्रों का अभिमत है। पूर्णिमा प्रदोषकाल में होती है तभी होलिका दहन होना चाहिए। अगले दिन पूर्णिमा है पर प्रदोषकाल में नहीं है। इसलिए दो को होगा। हालांकि दो को भद्रा भी है और भद्रा पूरी रात और सुबह 5.30 बजे तक रहेगी। निर्णय सिंधु और धर्मसिंधु के अनुसार भद्रा में राखी और होली नहीं मनाते हैं। इस पर शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा के मुख को छोड़कर होलिका दहन कर सकते हैं। प्रदोषकाल में भद्रा का मुख छोड़कर दो मार्च को शाम 6.28 से रात 8.52 तक होली जलाई जा सकती है। अगले दिन तीन मार्च को पूरे भारत में है चंद्रग्रहण है।

ग्रहण दोपहर 3 बजकर 21 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय शाम 6.30 बजे होगा और फिर शाम 6.47 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। इस दिन सूतक भी रहेगा। सुबह 6.30 से शाम को 6.47 तक सूतक रहेगा। इस समय में धुलेंडी मनाई जा सकती है और रंग खेल सकते हैं। डॉक्टर विनायक पांडे ने बताया कि पर्वकाल का महत्व है और प्रदोषकाल की तिथि व्यास होनी चाहिए। दो दिन पूर्णिमा है लेकिन जिस दिन प्रदोषकाल होता है तभी होलिका दहन होता है। यदि ग्रहण नहीं होता तो तीन मार्च को ही होलिका दहन होता और चार मार्च को धुलेंडी होती।

### दो मार्च को शाम 6 से 8 का शुभ मुहूर्त

मंत्र ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के अध्यक्ष आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया कि इस वर्ष तीन मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त था लेकिन इसी दिन चंद्रग्रहण आ रहा है। वहीं पूर्णिमा ग्रहणकाल और प्रदोष के पूर्व में ही समाप्त हो रही है। इस तरह की स्थिति में धर्मसिंधु के अनुसार दो मार्च को ही होलिका दहन प्रदोषकाल में करना होगा और तीन मार्च को धुलेंडी होगी। दो मार्च को शाम 6 से रात्रि 8 बीच प्रदोष काल का समागम होगा। यह सबसे अच्छा समय होगा होलिका दहन का। यदि ग्रहण नहीं होता तो तीन मार्च को ही दहन होता और चार मार्च को होली खेली जाती।